newsjankalyanseva@gmail.com

साप्ताहिक

जनकल्याण सेवा

ठाणे | वर्ष - २२ | अंक - ४७ | ११ से १७ दिसंबर २०२३ | पृष्ठ - ४ | कीमत : २ रु. | Postal Reg. No. PLG/08/2022-2024

संपादकीय

संपादक सीमा गुप्ता

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर समाज, पुलिस-प्रशासन और सरकारों के कामकाज की शैली को आईना दिखाया है। दर्ज मामलों पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक देखें तो आज भी हर जगह होने वाले अपराधों में महिलाएं सबसे ज्यादा जोखिम से गुजर रही हैं और उनके खिलाफ आपराधिक घटनाएं कम होने के बजाय और बढ़ रही हैं। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि २०२२ में देश भर में महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं के कुल चार लाख पैंतालीस हजार दो सौ छप्पन मामले दर्ज किए गए। जबकि इसके पिछले वर्ष यानी २०२१ में यह आंकड़ा चार लाख अट्ठाईस हजार दो सौ अठहत्तर और २०२० में तीन लाख इकहत्तर हजार पांच सौ तीन था। यानी वक्त बीतने के साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तस्वीर में कोई सुधार आने के बजाय स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। माना जाता है कि शहरों में कानून-व्यवस्था से लेकर अन्य उपायों की वजह से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से स्थितियां बेहतर हैं। मगर विडंबना है कि गांवों के मुकाबले शहरों और महानगरों में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हुई है। स्त्रियों का जीवन महानगरों में अपेक्षया ज्यादा जोखिम से गुजर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में दिल्ली सबसे ऊपर रही, जो लगातार तीसरे साल उन्नीस महानगरीय शहरों में सबसे अधिक है। राज्यों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे ज्यादा प्राथमिकी दर्ज हुई। जिस दौर में देश के हर स्तर पर आगे बढ़ने और व्यवस्था में बड़े बदलाव का हवाला दिया जा रहा है, उसमें महिलाओं के जीवन पर जोखिम में लगातार बढ़ोतरी कैसे हो रही है! आमतौर पर सभी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक घोषणाएं करती रहती हैं। मगर साफ देखा जा सकता है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से लेकर जितने भी कदम उठाए जाते हैं, उससे जमीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन को सहज और सुरक्षित बनाने में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है। आखिर क्या कारण है कि आज भी घर से बाहर आवाजाही के रास्तों से लेकर काम की जगहों, यहां तक कि घरों के भीतर भी महिलाओं को बहुस्तरीय जोखिम का सामना करना पड़ रहा है? हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य वारदात का शिकार होने को गंभीर अपराधों की श्रेणी में माना जाएगा, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ ३१.४ फीसद आपराधिक घटनाएं पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की थीं। सवाल है कि वक्त के साथ चतुर्दिक विकास, नए सख्त कानूनी प्रावधान और व्यवस्थागत सुधार के बीच महिलाएं कहां हैं? आमतौर पर सभी पार्टियों का यह चुनावी नारा और वादा होता है कि वे सत्ता में आने पर हर स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। मगर हकीकत यह है कि हर अगले साल एनसीआरबी के आंकड़ों से लेकर सभी अध्ययनों में यही अफसोसनाक तस्वीर होती है कि महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित और सहज महसूस नहीं कर पातीं। कानून-व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के भीतर शायद ही कभी खौफ दिखता हो। सामाजिक विकास का सवाल हाशिये पर होने की वजह से आम लोगों के भीतर भी स्त्रियों और उनके मुद्दों को लेकर जरूरी संवेदनशीलता का अभाव दिखता है। अगर देश की महिलाएं हर जगह खुद को असुक्षित पाती हैं, तो विकास के आंकड़ों और दावों का क्या मतलब रह जाता है?

रामभक्तो की आयोध्या पदयात्रा पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : आज पूरे देश में 'जय श्री राम' का माहौल है. हम जहां भी जाते हैं, हमें भगवान श्री राम के जयकारे सुनाई देते हैं। ये माहौल पूरे देश में है. अयोध्या के दर्शन के लिए लोग बडी संख्या में हवाई जहाज, ट्रेन, कार या इससे भी अधिक संख्या में अयोध्या जाते हैं। लेकिन यह अत्यंत प्रशंसनीय है कि आप मीरा भयंदर से अयोध्या तक पैदल चलने का त्याग कर रहे हैं। यह एक कठिन परीक्षा है. यह एक आसान लक्ष्य नहीं। लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद से यह आसान होगा और मीरा भयंदर के ३०० राम भक्तों की अयोध्या पदयात्रा पूरी तरह सफल होगी, ऐसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अयोध्या में एक अलग ही ऊर्जा है और जब हम श्री रामलला के दर्शन करते हैं तो हमें और अधिक शक्ति मिलती है, एक सुखद अनुभूति होती है. तभी हजारों की संख्या में मौजूद रामभक्तों ने 'जय श्री राम' का नारा लगाया. २२ जनवरी २०२४ को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा और श्री राम का मंदिर भक्तों के लिए खुला रहेगा। इससे करोडों श्रीराम भक्तों में खुशी है। आज १० दिसंबर को मीरा भयंदर के ३०० श्री राम भक्तों ने मीरा रोड

से श्री क्षेत्र अयोध्या राम जन्मभूमि तक पदयात्रा शुरू की। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे और विधायक प्रताप सरनाईक खुद शामिल हुए. करीब ४५ दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद श्रीराम भक्तों की यह पदयात्रा २२ जनवरी तक अयोध्या पहुंचने की कोशिश करेगी. ये तीर्थयात्री अयोध्या में नए मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। आज जब हाईवे के पास इस पदयात्रा का शुभारंभ हुआ तो मुख्यमंत्री मौजूद थे। सभी के हाथों में भगवा टोपी, जय श्री राम के नारे, हाथों में भगवा झंडे थे और माहौल भगवामय हो गया था. विधायक सरनाईक ने इन तीर्थयात्रियों को ४७ दिनों की पदयात्रा के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां दी हैं और पदयात्रा के दौरान प्रताप सरनाईक फाउंडेशन की एम्बुलेंस इन ३०० भक्तों के पीछे लगातार सेवा में रहेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज मैं उन ३०० श्रद्धालुओं का अभिनंदन करने आया हूं जिन्होंने अयोध्या चलने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने इस पदयात्रा के लिए ३०० श्रद्धालुओं के आयोजन और सहयोग के लिए विधायक प्रताप सरनाईक को बधाई दी. उन्होंने राम भक्तों से कहा कि हम पूरी ताकत से आपके साथ हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि करोडों श्रीराम भक्तों का सपना है कि अयोध्या में भव्य-दिव्य राम मंदिर बने. शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का भी यही सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ करोडों राम भक्तों और बाला साहेब का सपना पूरा किया है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। हर घर मोदी की तरह अब देश में मैन मैन मोदी का माहौल है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को

शेष पृष्ठ २पर

विधायक गीता जैन ने पियुष गोयल से की मुलाकात नमक विभाग को लेकर

जेकेएस संवाददाता

भाईंदर: मीरा-भाईंदर शहर विकास परियोजना में, शहर की नमक खदानों में सडकें प्रस्तावित की गई हैं, और चूंकि नमक विभाग के पास ये जगहें हैं, इसलिए इन पर सडक़ों का विकास रोक दिया गया है। साथ ही नगर पालिका ने शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान पर एक स्टेडियम आरक्षित कर दिया है. चूंकि यह मैदान भी नमक विभाग के स्वामित्व में है, इसलिए इस पर स्टेडियम का विकास रुका हुआ है। इन दोनों सीटों को नगर पालिका में स्थानांतरित करने या आरक्षण देने की मांग की गई है। गीता जैन ने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से संपर्क किया। गोयल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार करने मीरा- भायंदर आए थे। इससे पहले, जब वे उत्तन के रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में थे, जैन ने उनसे मुलाकात की और उन्हें उपरोक्त मांग दी। उस समय हुई चर्चा में भायंदर पश्चिम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान को मनपा के सिटी डेवलपमेंट प्लान में स्टेडियम रिजर्वेशन नंबर ९१ रखा गया है. पूर्व में इस मैदान के क्षेत्र में नमक का उत्पादन किया जा रहा था. हालाँकि अब इस पर नमक का उत्पादन नहीं होता है, केंद्रीय नमक विभाग इस साइट का मालिक है। इसी तरह भयंदर पश्चिम में बोस मैदान से मीरारोड रेलवे स्टेशन तक का क्षेत्र भी खारा है. विभाग के स्वामित्व में है। शहर विकास योजना के तहत इस क्षेत्र में सडकें प्रस्तावित की गई हैं। ये सडकें ५,९३५.३९ वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित हैं. यहां बोस मैदान और मोरवा गांव के बीच २,७१८० वर्ग मीटर क्षेत्र में सडकें भी प्रस्तावित की गई हैं। चूंकि ये सभी स्थल केंद्रीय नमक विभाग के स्वामित्व में हैं, इसलिए नगर पालिका इन स्थलों पर संबंधित विकास कार्यों के लिए अक्सर नमक विभाग के साथ पत्र-व्यवहार करती रही है। लेकिन जैन ने गोयल को बताया कि नमक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले कुछ सालों में शहर की जनसंख्या के साथ-साथ जनसंख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, बढते यातायात के लिए वैकल्पिक एवं पर्याप्त सडकें उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है।

भाजपा की योजनाएं और प्रचार का अभियान जारी

जेकेएस संवाददाता

भायंदर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी गाडी ने देश के हर गरीब और सामान्य व्यक्ति के भविष्य को उज्ज्वल करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से देश की जनता के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसका मकसद आम और गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है। उनके प्रचार-प्रसार के लिए ही 'विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है. इस बीच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को मीरा रोड स्थित सम्राट अशोक विपश्यना केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यह अभियान शनिवार से एकदशी एकादशी भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर शुरू किया गया है। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले, राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, श्री. गीता जैन, मनपा आयुक्त संजय काटकर, अपर आयुक्त, अनिकेत मनोरकर, सिटी इंजीनियर दीपक खाम्बित, भाजपा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा, पूर्व महापौर ज्योस्ना हसनले, डिंपल मेहता, पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट. रवि व्यास एवं अन्य उपस्थित थे। हाल ही में चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली सफलता के कारण बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम ४०० सीटें हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी पृष्टभूमि में भाजपा ने शनिवार को देवेश्वर भारत संकल्प यात्रा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किये गये विभिन्न विकास कार्यों के साथ-साथ लागू की गयी कई सफल योजनाओं का प्रचार किया. पूरे देश में इसकी शुरुआत एकदशी से हुई है गोयल ने कहा कि यह अभियान अगले डेढ.से दो महीने तक जारी रहेगा. इस संकल्प यात्रा के जरिए मोदी उन्होंने उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से देशभर के उन लाभार्थियों से संवाद करने की अपील की, जिन्हें अभी तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। पिछले १५ अगस्त को मोदी ने देश के २ करोड.आम लोगों को लखपति बनाने का संकल्प लिया है. देश में मोदी सरकार के दौरान महिलाओं को १० करोड. से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए। ४ करोड.से अधिक पक्के मकान बनाकर महिलाओं का सम्मान किया। करीब ३ करोड. घरों में बिजली पहुंचाई गई. चूंकि यह संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आयोजित की गई थी, इसलिए इसकी योजना मीरा- भाईंदर में बनाई गई.

अवैध विज्ञापनो के लिए आयुक्त ने की नोडल अधिकारी की नियुक्ती

जेकेएस संवाददाता

भायंदर: मीरा-भायंदर शहर में अनाधिकृत विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगाने के लिए नगर निगम ने आखिरकार सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जायेगी. इसके अलावा प्रशासन ने विज्ञापन छापने वाले मुद्रकों पर भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. नगर निगम से चार शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए वर्षों पहले सार्वजनिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं इन विज्ञापनों के लिए कुल ३४० सीटें तय की गई थीं. प्रत्येक विज्ञापन को अनुमति देने के लिए नगर निगम से उचित राशि ली जानी थी। लेकिन नियमों का पालन नहीं होने के कारण अनाधिकृत विज्ञापन जारी है ऐसा होता दिख रहा है. इस विज्ञापन के लिए जीवित पेडों और बिजली के खंभों का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिणामस्वरूप नगर की विकृति में भी भारी वृद्धि हो रही है। तो अब मनपा आयुक्त संजय काटकर ऐसे अवैध विज्ञापनों पर ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. इसमें विज्ञापन पर नियंत्रण के लिए अब प्रत्येक वार्ड अधिकारी को 'नोडल अधिकारी' नियुक्त किया गया हैं. विज्ञापन को लेकर सरकार और कोर्ट ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया. दिए गए नियमों का सख्ती से पालन करेंइसका संकेत दिया गया है. इसके अलावा इस कार्य की नियमित रिपोर्ट शासन को भेजनी है। कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि अगर यह जानकारी देने में देरी हुई तो सीधे कार्रवाई

की जायेगी. यह अनुमान लगाया गया है कि शहर में अनधिकृत विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जाएगा। पूर्व में भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम नागरिकों की शिकायत पर अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज किये गये हैं.

मीरा-भायंदर शहर में बडी संख्या में अनाधिकृत विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना नगर निगम को भनक तक नहीं लगी। इसलिए नगर महासभा के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि शहर में लगाए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर बारकोड के रूप में मुद्रक का नाम और उसके कार्यालय का पता लिखना अनिवार्य है। लेकिन प्रशासन इन नियमों को लागू करने से मुंह मोड.रहा था. अब कमिश्नर संजय काटकर ने इन नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है. इसी के तहत नगर पालिका की ओर से शहर में विज्ञापन छापने वाले मुद्रकों को नए नोटिस जारी किए गए हैं। ऐलान किया गया है कि ऐसा नहीं करने पर सीधी कार्रवाई की जायेगी.

मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की असली नायक के रूप में प्रशंसा की

जेकेएस संवाददाता

मुंबई : पालिका के सफाई कर्मचारी मुंबई को साफ रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं , उन्हीं की वजह से मुंबई स्वच्छ और सुंदर है और मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की ' असली नायक ' के रूप में प्रशंसा की। इस अभियान के माध्यम से मुंबई की संपूर्ण मुख्य सड़कों , आंतरिक सड़कों , आंतरिक कॉलोनियों की गहन सफाई की जा रही है। इसके लिए हम पानी पीते हैं यदि उपयोग नहीं किया गया पुनर्चक्रित जल का उपयोग करता है। इस अभियान में चार से पांच वार्डों के कम से कम दो हजार लोगों के एक समय में एक क्षेत्र में काम करने से क्षेत्र पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है. सड़कें , गंदा नाला , नालियाँ सार्वजनिक शौचालय साफ.हो रहे हैं. मलिन बस्ती सुधार योजना की श्री शिंदे ने इस समय कहा कि इसमें इसे भी शामिल किया गया है.

शाहजी राजे म्युनिसिपल स्कूल के विद्यार्थियों के चित्रों की सराहना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समग्र स्वच्छता अभियान के तहत विले पार्ले (पूर्व) में नेहरू मार्ग की सफाई का निरीक्षण किया और स्वच्छता अभियान में भाग लिया. शाहजी राजे स्कूल विद्यार्थियों से बातचीत की। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों का निरीक्षण कर सराहना की गई। स्कूल के विद्यार्थियों ने लाजिम और ढोल की थाप पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इस मौके पर छात्र-छात्राएं मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़े.

मुख्यमंत्री ने कांदिवली पूर्व स्थित ठाकुर संकुल सोसायटी में आयोजित स्वच्छता जागरूकता रैली को संबोधित किया. इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने स्वच्छता पर एक नुक्कड़.नाटक प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों से बातचीत की और उनकी सराहना की। संरक्षक मंत्री दीपक केसरकर , सांसद गोपाल शेट्टी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अंधेरी पूर्व में गोखले फ्लाईओवर का निरीक्षण

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुबह अंधेरी पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाले गोपालकृष्ण गोखले रेलवे फ्लाईओवर के काम का निरीक्षण किया। इस पुल का पहला गर्डर हाल ही में रखा गया है। इस पुल के पहले मार्ग को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने संबंधितों को निर्धारित समय के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।

रामभक्तो की आयोध्या पदयात्रा पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

पृष्ठ १ का शेष

भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अयोध्या का विकास कर पूरा नक्शा ही बदल दिया है। मोदी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम किया है। उन्होंने योगीजी के काम की सराहना करते हुए कहा, 'बुलडोजर चलता है वो'. मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि विधायक प्रताप सरनाईक ने धर्मवीर आनंद दिघे साहब को याद किया. आनंद दिघे साहब ने १९८७ में अयोध्या के लिए चांदी की ईंट भेजी थी. तब हम साथ थे. धर्मवीर आनंद दिघे साहब को पता था कि एक दिन अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और करोडों लोगों का सपना साकार होगा. कई लोगों को लगता था कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर नहीं बनेगा और विरोधियों ने सवाल उठाया कि मंदिर कब बनेगा. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर भी बना लिया है और उसके उद्घाटन की तारीख भी घोषित कर दी है, इसलिए इसके खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद हो गया है. २२ जनवरी को देशभर से लोग अयोध्या आएंगे. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर जैसे अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं। देश का नाम दुनिया में चमक रहा है. हमें गर्व है कि आज देश का नाम दुनिया में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। ४५ दिनों तक पैदल चलना कोई सामान्य बात नहीं है. लेकिन ३०० पदयात्री आपको श्री राम और हनुमान की शक्ति देंगे। आपका हर जगह स्वागत होगा. आपको प्रेरणा और उत्साह मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पैदल चल रहे लोगों से वादा किया कि वह राम मंदिर के उद्घाटन के दिन अयोध्या में इन ३०० लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। भाषण की शुरुआत और अंत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'जय श्री राम' का नारा लगाकर भक्तों का उत्साह बढाया. विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री को प्रणाम कर सम्मानित किया.

अमदार सरनाईक ने जगाई आनंद दिघे की यादें....

यह तथ्य कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर खडा है, यह सभी हिंदुओं और श्री राम भक्तों के लिए जीवन की सबसे बडी बात है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन शुरू होने से पहले, ठाणे शहर चांदी की ईंटें देने वाला पहला शहर था। पहली चांदी की ईंट १९८७ में शिवसेना के तत्कालीन ठाणे जिला प्रमुख स्वर्गीय आनंद दीघे साहब के माध्यम से ठाणे शहर से अयोध्या भेजी गई थी। आनंद दिघे कट्टर हिंदूवादी माने जाते थे. उस समय राम मंदिर निर्माण को लेकर शिव सेना सबसे आगे थी. एकनाथ शिंदे इस सारी घटना के गवाह थे. शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने श्री राम मंदिर निर्माण का खुलकर समर्थन किया था. तो बिना किसी के ध्यान के, वास्तव में, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पांच साल पहले, आनंद दीघे साहब ने १९८७ में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पहली चांदी की ईंट बनाई थी। विधायक सरनाईक ने कहा कि उस ईंट पर 'जय श्री राम' लिखा था, यह सिर्फ ठाणेकर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के राम भक्तों को याद है. वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे उस समय के गवाह हैं जब चांदी की ईंट अयोध्या भेजी गई थी। विधायक सरनाईक ने कहा, इसलिए, मुख्यमंत्री ने मीरा भयंदर से ३०० राम भक्तों का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने का फैसला किया, जब वे अयोध्या जा रहे थे और वह स्वयं इसमें शामिल हुए।

मीरारोड में प्रदर्शन दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग

मीरारोड : करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेवसिंह गोगामेडी के निर्मम हत्या के विरोध में शिवसेना मीरा – भायंदर राजस्थानी सेल द्वारा एमएलए प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में १४५ मीरा भायंदर विस प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह और कपिल परमार के नेतृत्व में सैकडों व्यापारियों, छत्तीसी कौम समाज व अन्य सभी वर्ग के लोगों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर सुखदेव गोगामेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद लोगों ने हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग को लेकर पूरे शांति नगर परिसर में पदयात्रा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया, जिससे समाज व उनके परिवारजनों को न्याय मिल सके. इस दौरान जिला प्रमुख, राजस्थानी समाज अध्यक्ष कपिल परमार, जिला सचिव जगदीश नाईक, महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह भाटी, गुजराती सेल की महिला अध्यक्ष चेतना आचार्य, सतीश सिंह, शाखा प्रमुख सुरेंद्र राजपुरोहित, चंद्रकांत पांचाल महिपाल सिंह व अन्य व्यापारी वर्ग के कई नेतागण उपस्थित थे.

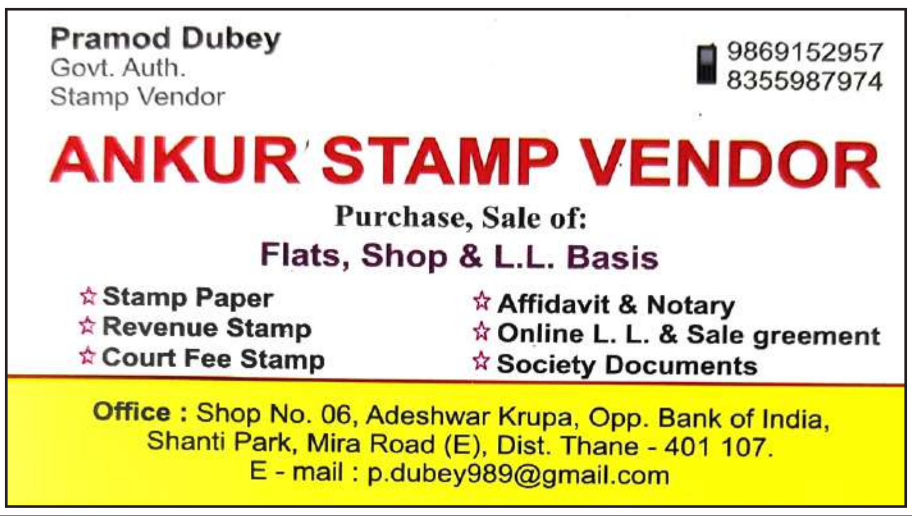

भाजपा का हल्लाबोल, विर सावरकर के खिलाफ के बयान पर विवाद

जेकेएस संवाददाता

भायंदर: कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ दिए अपने बयान को लेकर विवाद खडा हो गया है । ऐसे बयानों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज पांडे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रियांश खड़के के पुतले पर चप्पल जूते चला कर विरोध प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, मीरा भायंदर १४५ के प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास तथा युवा मोर्चे के अध्यक्ष पंकज पांडे की उपस्थिति में हुए विरोध प्रकट कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारे बाजी की ! प्रियांक ने अपने बयान में कहा कि अगर वह प्रभारी होते तो बेलगावी में सुवर्ण सौधा विधानसभा से वीर सावरकर की तस्वीर हटवा देते। साथ ही कहा की उनका योगदान क्या है ? हालाकि उन्होंने यह अपनी निजी राय बताई है। वीर सावरकर का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान से इंकार नहीं किया जाता लेकिन कांग्रेस के इस बडब्रोलेपन ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।

यह सरकार सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है प्रत्यक्ष कार्य करने वाली सरकार –संरक्षक मंत्री शम्भुराज देसाई

ठाणे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य सरकार आम आदमी के लिए काम करने वाली सरकार है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकारी तंत्र सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। हर जरूरतमंद लाभार्थी की तलाश की जा रही है। उन्हें योजना समझाई जा रही है और वास्तविक लाभ भी दिया जा रहा है। इससे अब लाभार्थियों को परेशानी नहीं हो रही है। इससे एक बात निश्चित रूप से साबित हो गई है कि यह सरकार केवल घोषणा करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि सीधे काम करने वाली सरकार भी है, यह बात आज यहां राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री और ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री शंभुराज देसाई ने कही। वह भिवंडी तालुका के काल्हेर ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम धविकसित भारत संकल्प यात्राध और धटेलीविजन प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधान मंत्री की सीधी बातचीतध के अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री श्री कपिल पाटिल, कलेक्टर अशोक शिंगारे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, डिप्टी कलेक्टर (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ थोम्ब्रे, परियोजना निदेशक डॉ. छायादेवी शिसोडे, भिवंडी के जिला मजिस्ट्रेट अमित सनप, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) प्रमोद काले, जिला सर्जन डॉ. डॉ. कैलास पवार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी। गंगाधर पारगे, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी दीपक कुटे, दूरदर्शन निदेशक सिद्धार्थ बोडके, तहसीलदार अचिस पाटिल, जी.पी. महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय बागुल, स्वास्थ्य निदेशालय के सहायक निदेशक डॉ. चाकुरकर, केंद्रीय संचार ब्यूरो, पुणे के प्रबंधक डॉ. जितेंद्र पानपाटिल, समूह विकास अधिकारी प्रदीप घोरपडे, स्थानीय जन-प्रतिनिधि, ग्रामीण, विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। पालक मंत्री श्री देसाई ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए धविकासित भारत संकल्प यात्राध की अवधारणा को लागू करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर देशभर में जागरूकता का माहौल बना हुआ है. इसी अवधारणा के आधार पर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्रियों देवेन्द्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के मार्गदर्शन में धशासन आपके द्वारध की अवधारणा को पूरे राज्य में बडे.उत्साह के साथ लागू किया जा रहा है। अब तक सरकार करीब एक करोड.७५ लाख लाभार्थियों तक पहुंचने में सफल रही है. पालक मंत्री श्री देसाई ने इस कार्यक्रम की अच्छी योजना बनाने के लिए कलेक्टर अशोक शिंगारे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने जिला प्रशासन को अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ पहुंचाने के कार्य में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की शुभकामनाएं दी और अंत में सभी को आश्वस्त किया कि किसी भी सरकारी योजना में सामंजस्य लाने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो शर्तों, नियमों में आवश्यक बदलाव करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किये जायेंगे. और उस योजना की शर्तें।

विकासित भारत संकल्प यात्राध आम लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी - केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल

इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना पर पूरे भारत में धविकसित भारत संकल्प यात्राध का आयोजन किया गया है. हर जरूरतमंद लाभार्थी को ढूंढना, उसे योजनाओं की जानकारी देना, उसे तुरंत वास्तविक लाभ दिलाना, इस तरह का काम इस पहल के माध्यम से हो रहा है। सरकार और सरकारी तंत्र लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साढे.नौ साल में एक आम नागरिक के तौर पर जिस तरह से काम किया है, वह देशवासियों के प्रति उनकी निष्ठा और चाहत को दर्शाता है। यह सरकार गरीबों, जरूरतमंदों को समर्पित है और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इससे सभी भारतीयों में यह विश्वास जागृत हुआ कि धहमारा भारत एक महाशक्ति बनेगाध। इसके साथ ही श्री पाटिल ने घोषणा की कि १ जनवरी २०२४ से ठाणे जिले की ४५२ ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.

इस कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्टर ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन का प्रत्येक सरकारी विभाग धविकासित भारत संकल्प यात्राध के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचेगा और उन्हें सरकार का आवश्यक लाभ प्रदान करेगा। उन लाभार्थियों को योजना. इस कार्य में ठाणे जिला अग्रणी रहेगा।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) श्री प्रमोद काले ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई।

भिवंडी पंचायत समिति के विषय विशेषज्ञ डॉ. विनायक पाटिल और चिकित्सा अधिकारी डॉ. तारुलता धानके द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर विकसित भारत की संकल्पना पर सामूहिक शपथ ली गयी.

स्थानों में भारतीय स्टेट बैंक-अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री उज्वला योजना, सही पोषण देश रोशन, स्वास्थ्य विभाग-आयुष्मान भारत योजना, खेल-बैडमिंटन प्रशिक्षण, प्रधान मंत्री आवास योजना, आदिवासी विकास परियोजना, शाहपुर, कीटनाशक शामिल हैं। ड्रोन द्वारा छिडक़ाव प्रदर्शन विषय से संबंधित स्टॉल लगाए गए। यहीं पर लाभार्थियों का पंजीयन भी किया गया।

यात्रा भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेलीविजऩ संवाद से प्रेरित हुए काल्हेर के ग्रामीण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से कर्नाटक, गुजरात, चंडीगढ, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड जैसे विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस बातचीत के माध्यम से, श्री मोदी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और योजनाओं के लाभों के संबंध में लाभार्थियों के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जाना। 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' से देशभर के नागरिक जुड.गए हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि हर भारतीय 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए जी-जान से प्रयास कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए वंचितों तक योजनाओं की जानकारी और वास्तविक लाभ पहुंचाया जाए. प्रधानमंत्री की इस बातचीत से काल्हेर के ग्रामीण काफी प्रेरित दिखे.

मन ओपस बिल्डिंग में सुविधाओं का अभाव उठा विवाद, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में दायर की गई है याचिका

मीरारोड : हरित लवादा खंडपीठ के आदेश से धमन ओपसध बिल्डिंग में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से बिना प्रक्रिया किए अशुद्ध गंदे जल को १० एचपी मोटर द्वारा सीधे मनपा के गटर में छोडे.जाने आदि का निरीक्षण खंडपीठ द्वारा गठित समिति ने किया। मन ओपस बिल्डिंग मीरा भायंदर मनपा की सीमा में काशीमीरा परिसर में बनाई गई है। इस बिल्डिंग के निर्माण के दौरान पर्यावरण नियमों के उल्लंघन किए जाने के आरोप में पुणे पश्चिम खंडपीठ के समक्ष पर्यावरण प्रेमी इरबा कोनापुरे और साबिर सैयद ने याचिका दायर की है। हरित लवादा की खंडपीठ के आदेश पर इस बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए गठित चार सदस्यीय समिति में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का समावेश है। खंडपीठ के समक्ष दायर की गई याचिका में इतने बडे.आवासीय परिसर में मनोरंजन का कोई मैदान नहीं होने, मैदान को पोडियम पर एक बंद जगह में दिखाने, इसके अलावा आवास परिसर में घन कचरा प्रकल्प नहीं बनाने ,कचरे को सीधे मनपा के डंपिंग ग्राउंड में ले जाए जाने आदि मुद्दों की शिकायत की गई है। साथ ही २० हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बोरिंग के जरिये पानी खींचने , हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सोलर पैनल सिस्टम लगाना अनिवार्य होते हुए भी नही लगाए जाने, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम कार्यरत नहीं होने,बगीचा विकसित नहीं करने,पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू नहीं करने तथा इसकी पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं करने आदि की शिकायत भी याचिका में की गई है, ऐसी जानकारी याचिका कर्ता पर्यावरण प्रेमी इरबा कोनापुरे ने दी है।

जनकल्याण सेवा की संपादिका सीमा गुप्ता चाय पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य भाजपा किसान मोर्चा जौनपुर, ओबरा विधानसभा प्रभारी सोनभद्र अरविंद सिंह व प्रताप फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष व शिवसेना शिंदे गुट के जिलाप्रमुख विद्या चतुर्वेदी, उपजिला प्रमुख शिवसेना, उ.भा. डी. के. मिश्रा, शाखाप्रमुख मि.भा. मनोज बी. सिंह, व अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिती में चर्चा हुई .

मिरा - भाईंदर महानगरपालिका

उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग

दुसरा मजला, प्रभाग समिती क्र. ४, कै. विलासराव देशमुख भवन,
जांगिड इन्क्लेव्ह, कनकिया, मीरारोड (पुर्व), ता. जि. ठाणे ४०११०७,
दुरध्वनी क्र.२८१०३४०९

जा. क्र./मनपा/उद्यान/मिरारोड/७८३/२०२३-२४ दिनांक : ०८/१२/२०२३

// जाहिर नोटीस सुचना //

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम १९७५ च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या प्रकरण पाच कलम ८ (३) अन्वये या नोटीसीद्वारे असे जाहिर करण्यात येते की,खालील नमुद तक्त्यातील झाड काढणे करणेकामी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र	तपशिल		संख्या	तपशील
१	मलनि:सारण केंद्र क्र. ०७, आला हजरत मैदानाच्या बाजुला, मिरारोड (पु.) येथे उंच जलकुंभ बांधणे कामामध्ये बाधित झाडे मुळासहित काढणे / पुर्न:रोपण करणे.	मुळासहित काढणे	३७	मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभागाच्या मलनि:सारण केंद्र क्र. ०७, आला हजरत मैदानाच्या बाजुला, मिरारोड (पु.) येथे उंच जलकुंभ बांधणे कामामध्ये सदर झाडे बाधित होत असुन झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपण करणे आवश्यक आहे. कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग) यांचे दि.०१/१२/२०२३ रोजीचे पत्र.
		पुर्न:रोपण करणे	०३	
		एकुण	४०	
२	राणी लक्ष्मीबाई उद्यान (आरक्षण क्र. २०१) (बगीचा), पुनमसागर, मिरारोड (पु.) येथे उंच जलकुंभ बांधणे कामामध्ये बाधित झाडे मुळासहित काढणे / पुर्न:रोपण करणे	मुळासहित काढणे	०८	मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभागाच्या राणी लक्ष्मीबाई उद्यान (आरक्षण क्र. २०१) (बगीचा), पुनमसागर, मिरारोड (पु.) येथे उंच जलकुंभ बांधणे कामामध्ये सदर झाडे बाधित होत असुन झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपण करणे आवश्यक आहे. कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग) यांचे दि.०१/१२/२०२३ रोजीचे पत्र.
		पुर्न:रोपण करणे	१९	
		एकुण	२७	

सदर प्रस्तावित वृक्ष तोडण्याची / स्थलांतरीत करण्याची परवानगी देण्याचा इरादा आहे. याबाबत नागरिकांच्या काही हरकती तसेच सदर वृक्षांवर पक्षांची घरटी असल्यास जाहिर सुचना प्रसिद्ध झाल्यापासुन ७ दिवसाच्या आत लेखी स्वरुपात उप-आयुक्त (उद्यान), उद्यान विभाग, मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.) येथे किंवा garden@mbmc.gov.in किंवा mbmc.garden@gmail.com ई-मेल आयडी वर कळविण्यात यावे. सबब विस्तृत माहिती महापालिका संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सुचनांचा विचार केला जाणार नाही याची कृपया नोंदी घ्यावी.

सही/-
(योगेश गुणिजन)
सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

जा. क्र. मनपा/मावज/ई-१११८८४१/ २०२३-२४
दिनांक १०/१२/२०२३

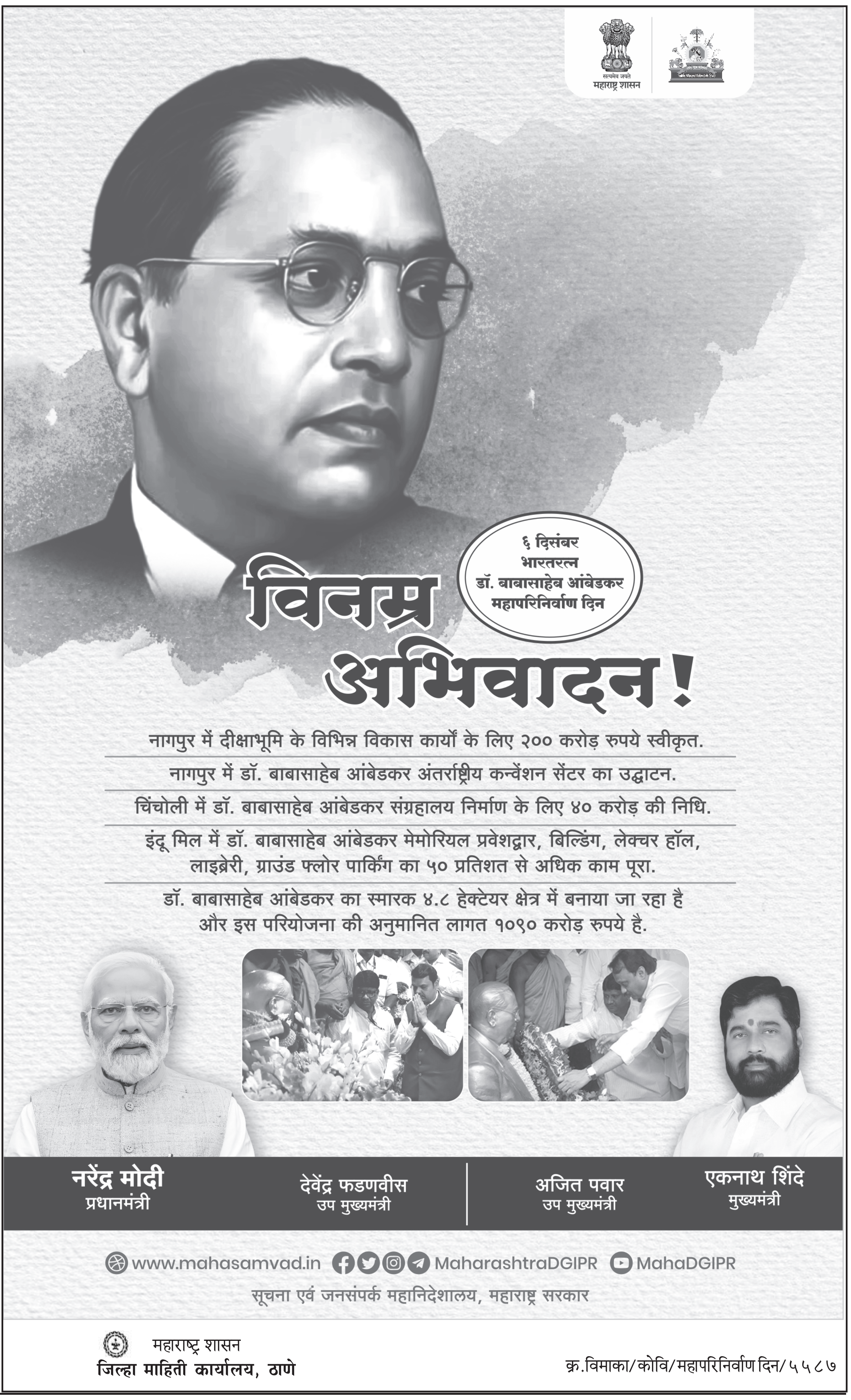

मनपा कर रही है भेदभाव, अवैध पार्टी के कार्यालय छुपा रही है और अवैध निर्माण तोड रही है

जेकेएस संवाददाता

भायंदर । नेताओं के अवैध कार्यालयों की सूची मीरा भायंदर मनपा ने तैयार तो कर ली है,लेकिन उसे सार्वजनिक करने की हिम्मत जुटा नही पा रही है ।इसलिए उसे छिपाना शुरू कर दिया है ।जबकि लोगों के अवैध निर्माण की सूची जारी कर दी है। हालांकि अवैध निर्माण की सूची में सवाल खडे. किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के कंटेनर शाखा के बाद शहर में राजनीतिक दलों और नेताओं के अवैध कार्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई ।इसके लिए मीरा भायंदर मनपा ने उनकी सूची बनानी शुरू की ।शनिवार तक सूची बनाने का काम पूरा भी हो गया। लेकिन उसे सार्वजनिक करने की हिम्मत प्रशासन जुटा नहीं पा रहा है। अवैध निर्माण नियंत्रण विभाग के प्रमुख नरेंद्र चव्हाण से पत्रकार सोमवार से अवैध कार्यालयों की सूची मांगते आ रहे हैं ।लेकिन वे कोई न कोई बहाना देकर टाल देते रहे हैं। हमारे संवाददाता ने मंगल और बुधवार को उनसे दो बार संपर्क किया। पहले उन्होंने बाद में देने और फिर आयुक्त से मांग कर लेने की बात कही। जबकि लोगों के अवैध निर्माण बिना किसी के मांगे ही सार्वजनिक किए गए,जो अच्छी बात है ।आयुक्त संजय श्रीपतराव काटकर को हमने मैसेज भेजकर इससे अवगत कराया। लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। मालूम हो,शहर में राजनीतिक पार्टियों के अवैध कार्यालयों धडल्ले से बने हैं।२०१९ में हुए सर्वेक्षण में राजनीतिक दलों और नेताओं के ४६ अवैध कार्यालय पाए गए थे ।आमसभा ने उन पर कार्रवाई का निर्णय भी लिया था ।लेकिन कारवाई करने की प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई ।पिछले दिनों शिवसेना(शिंदे) की कंटेनर शाखा का जब कांग्रेस, उद्धव शिवसेना और मनसे ने विरोध किया,तब शिवसेना(शिंदे)ने पहले सभी अवैध कार्यालयों को हटाने और फिर कंटेनर को हाथ लगाने की धमकी दी। और प्रशासन उसे आज तक हिला नहीं पाया। दूसरी तरफ मीरा भायंदर मनपा ने शहर में हुए अवैध निर्माण की एक सूची तैयार की है,जिसमें सिर्फ १८३ अवैध निर्माण बताए गए हैं। इसमें प्रभाग १ में ६, २ में १, प्रभाग तीन में ७८, प्रभाग चार में ३२, प्रभाग ५ में ८ और प्रभाग ६ में ५८ अवैध निर्माण बताए गए हैं। इस आंकडे.को लेकर गोलमाल होने और आश्चर्य जताए जा रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत ने कहा कि यह सर्वेक्षण अधूरा लगता है ।कोर्ट में चल रहे मामलों से जुडे.अवैध निर्माण दिखाए गएं हैं।

जल परिवहन सेवा को स्थानांतरित करने की उठी मांग

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : शहर में जल परिवहन सेवा शुरू करने की कवायद जोर-शोर से शुरू हो गई है, जिससे भविष्य में शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों अपने निरीक्षण दौरे के दौरान मनपा आयुक्त एवं प्रशासक संजय काटकर से इस प्रोजेक्ट से संबंधित निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया था। इस जल परिवहन सेवा में सबसे बड़ा पेंच अब जैसल पार्क चौपाटी पर इस सेवा के लिए बनाए जाने वाले जेट्टी प्लेटफार्म को लेकर फंस गया है। अब इसे स्थानांतरित करने की मांग उठ रही है। इसके लिए कई संस्थाओं ने सीएम सहित अन्य विभागों को पत्र लिखा है। प्रस्तावित नई विकास नियंत्रण नियमावली

(डीपी प्लान) में जैसल पार्क चौपाटी (आरक्षण क्रमांक ८१) को जल परिवहन स्टेशन (जेट्टी) के रूप में आरक्षित किया गया है, जिसका न सिर्फ स्थानीय नागरिकों, अपितु तमाम जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों तथा सामाजिक संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में जीवदया एवं तमाम सामाजिक कार्यों को अंजाम देने वाली संस्था जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव एवं मीरा-भायंदर महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक संजय काटकर को पत्र लिखकर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के प्रमुख केंद्र जैसल पार्क चौपाटी से इस प्रस्तावित जल परिवहन सेवा के स्टेशन को कुछ और दूरी पर स्थानांतरित करने की मांग की है। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति के महासचिव डॉ नरेंद्र गुप्ता ने इस बारे में बताया कि हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जैसल पार्क चौपाटी न सिर्फ स्थानीय नागरिकों, अपितु समूचे मीरा-भायंदर के लोगों के लिए एकमात्र जीवनदायक स्थल है। जहां मीरा -भायंदर के नागरिक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आदि सुबह- शाम खाड़ी के किनारे स्वच्छ व खुली हवा में टहलने के लिए आते हैं। यहीं पर बच्चों के खेलने के लिए मैदान हैं। यहीं पर अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सरल शब्दों में जैसल पार्क चौपाटी एक ऐसा स्थल है, जहां पर यहां के लोगों की जिंदगी सांस लेती है। जिसे यहां के लोग किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। संस्था ने अपने पत्र में कहा है कि मीरा-भायंदर से जल-परिवहन प्रारंभ करने की महाराष्ट्र सरकार की यह योजना सराहनीय है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन मीरा-भायंदर के संशोधित डीपी प्लान से यह ज्ञात होता है कि इसमें जल-परिवहन टर्मिनल को (आरक्षण क्रमांक ८१) जैसल पार्क चौपाटी पर बनाया जाना प्रस्तावित है।

जलापूर्ति के लिए एमबीएमसी को करना होगा मई २०२४ तक इंतजार

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : बहु प्रतीक्षित सूर्य प्रादेशिक जलापूर्ति प्रकल्प से वसई विरार महानगरपालिका को प्रथम चरण में एमएमआरडीए ने जलापूर्ति की शुरुआत कर दी है। वहीं मीरा भायंदर वासियों को पर्याप्त जलापूर्ति के लिए अभी भी मई २०२४ तक इंतजार करना होगा। मीरा भायंदर शहर को इस प्रकल्प से जलापूर्ति के लिए दूसरे चरण में अब तक ८६% कार्य पूर्ण हुआ है। बाकी के कार्य पूर्ण करने में अभी ६ माह से अधिक का समय लगने वाला है, इसलिए दूसरे चरण में मई २०२४ तक मीरा भायंदर शहर को जलापूर्ति कार्यान्वित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सूर्या प्रकल्प से जलापूर्ति शुरू होने के बाद वर्ष २०५५ तक के लिए मीरा भायंदर वासियों की पानी की किल्लत दूर होने का दावा किया गया है। बता दें की वसई विरार और मीरा भायंदर की पानी समस्या के समाधान और पर्याप्त जलापूर्ति के लिए करीब १३२५.७८ करोड.रुपए की लागत से सूर्या प्रादेशिक जलापूर्ति योजना प्रकल्प शुरू की गई थी। इस प्रकल्प के अंतर्गत ४०३ एमएलडी जलापूर्ति की जाने वाली है। इस प्रकल्प की शुरुआत २०१७ में हुई थी। प्रायक्ष में इस प्रकल्प का कार्य शुरू होने के बाद ३४ महीने में इसे पूर्ण होना अपेक्षित था ,लेकिन भूसंपादन, कई विभागों से अनुमति प्राप्त करने आदि तांत्रिक अडच़नों के कारण यह कार्य धीमी गति से चल रही थी। जिससे इस प्रकल्प से जलापूर्ति शुरू होने में विलंब होते रही। वर्ष २०२१ के बाद एमएमआरडीए ने इस कार्य को गति दी। जिससे जून २०२३ में इस प्रकल्प के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हुआ और हाल ही में वसई विरार शहर को इस प्रकल्प से जलापूर्ति शुरू की गई है। जबकि मीरा भायंदर शहर वासियों को अभी भी पर्याप्त जलापूर्ति का इंतजार है। एमएमआरडीए के अधिकारियों के अनुसार द्वितीय चरण में ८६% कार्य पूर्ण हो चुका है ।सूर्या योजना के द्वितीय चरण में प्रकल्प कार्यान्वित करने के लिए १३२ केवी बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। इसके पोल लगाने और अन्य कार्यों के लिए वन विभाग की अनुमति मिल गई है जिससे इस कार्य में अब गति आएगी, बाकी का कार्य मई २०२४ तक पूर्ण हो जाएगी। यह चरण पूर्ण होने के बाद मीरा भायंदर शहर को प्रतिदिन २१८ एमएलडी पानी उपलब्ध होगी। १० जुलाई २०१७ को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूर्या प्रादेशिक पानी आपूर्ति योजना का मीरा रोड पूर्व के एस. के. स्टोन के पास आयोजित एक कार्यक्रम में विधिवत भूमिपूजन किया था। इस योजना से मीरा-भायंदर शहर को २१८ एमएलडी पानी आपूर्ति की जाएगी। ३४ महीने में इस योजना को पूर्ण कर २४ घन्टे पानी देने का आश्वासन भी उस समय दिया गया था। मीरा भायंदर शहर को स्टेम प्राधिकरण से ८६ एमएलडी और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) प्राधिकरण से १२५ एमएलडी ऐसे कुल २११ एमएलडी जलापूर्ति की मंजूरी है। जबकि प्रत्यक्ष में प्रतिदिन औसतन १८५ से १९० एमएलडी जलापूर्ति ही की जाती है। मनपा प्रशासन द्वारा मीरा भायंदर शहर की २० वर्षो की अंदाजित जनसंख्या और पानी की आवश्यकता का यह अनुमान लगाया था और पानी आपूर्ति के लिए चालू योजनाओ के पूरा हो जाने पर शहर में पानी की समस्या नही रह जाने का दावा किया है।

मीरा-भायंदर में पेड़ों की हत्या को लेकर वृक्ष प्रेमियों में गहरा आक्रोश

जेकेएस संवाददाता

भायंदर: नगर पालिका ने मीरा-भायंदर में तीन स्थानों पर सीवेज उपचार संयंत्रों के विकास और अतिरिक्त विकास के संबंध में १५४ पेडों को काटने का फैसला किया है और निविदा प्रक्रिया भी की जा चुकी है। अनुमान लगाया गया है कि काटे जाने वाले इन पेडों की कीमत १० लाख ८० हजार होगी. हालाँकि, जैसा कि स्रोत से बताया गया है कि एक पेड.को दोबारा लगाने की लागत लगभग १ से २ लाख है, भविष्य में अनुमानित लागत में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। पेडों की हत्या से शहर के वृक्ष प्रेमियों में काफी आक्रोश है. शहरी अपशिष्ठ जल का उपचार ऐसा करने के लिए, नगर पालिका विभिन्न स्थानों पर ११ सीवेज उपचार केंद्र शुरू किए हैं। हालांकि ये केंद्र अभी भी ठीक से नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने नए केंद्र और कुछ केंद्र अतिरिक्त रूप से विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे १५४ पेड. प्रभावित हुए. हल घुमाने का निर्णय लिया गया है और तत्कालीन प्रशासनिक बैठक में इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गयी है. पहले से स्थापित सीवेज उपचार संयंत्रों से सीवेज को बिना ठोस उपचार के निकटवर्ती सीवरों या नालियों में छोड. दिया जाता है। प्रदूषण चालू नियंत्रण निगम ने भी आपत्ति जताई और हालात नहीं सुधरने पर केंद्र बंद करने की चेतावनी दी। लेकिन चूंकि सरकार की चेतावनियाँ ज्य़ादातर कागजों पर ही रहती हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता यहाँ भी हुई। इसी तरह, नगर पालिका ने मीरारोड में अ-यप्पा मंदिर के निकट एक भूखंड, नंबर १५ बस स्टॉप के निकट एक भूखंड और भयंदर पूर्व में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निकट एक भूखंड का चयन किया है। अयप्पा मंदिर के पास सबसे बडा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से ही चल रहा है और अपशिष्ठ जल का उपचार भी बंद है। प्रशासन ने १५४ विभिन्न पेडों को काटने का निर्णय लिया है जो नए सीवेज उपचार संयंत्रों के विकास में बाधा बन रहे हैं। पहले भी नगर पालिका ने विभिन्न विकास कार्यों में बाधा डालने वाले पेडों का कत्लेआम किया है और मुआवजे के तौर पर कहां और कितने पेड.लगाए गए, इसका हिसाब-किताब वृक्ष प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन आंकडे.पेश कर समय बर्बाद किया जाता है. यह गहरा है. गीता जैन ने यह बात तत्कालीन वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के सामने की थी. इसके अनुसार हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम पर लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं नये पौधे खरीदकर नये सिरे से लगाये जाते हैं। चूँकि इनमें से कई पेडों का संरक्षण नहीं किया जाता, वे सूख जाते हैं और मर जाते हैं। इस वर्ष भी वैसी ही स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन इस बार कांग्रेस प्रशासन को अछूता नहीं छोडा जाएगा.
- प्रकाश नागाणे, कांग्रेस प्रवक्ता

सेमी सरकारी अस्पताल का होगा निर्माण, जनता को मिलेगी सुविधाएं

जेकेएस संवाददाता

भायंदर । मीरा भायंदर की जनता के लिए अच्छी खबर है ।दहिसर चेकनाका पर नाट्यगृह के पीछे मल्टी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। २३ जनवरी को बालासाहेब ठाकरे की जन्म जयंती पर इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों होगा।१०० बेड के इस सेमी सरकारी अस्पताल में पीला, केसरी,सफेद राशन कार्ड तथा आयुष्मान भारत कार्ड धारक परिवारों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस संबंध में मीरा भायंदर मनपा के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर व शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने संयुक्त रूप से जानकारी दी ।बताया कि मेडिकल इक्विपमेंट के लिए २५ करोड रुपए की निधि राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है ।इमारत का काम ९० फीसदी पूरा हो चुका है ।अस्पताल का संचालन निजी

एजेंसी करेगी ।अस्पताल को मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक नाम दिया गया है। उपायुक्त(स्वास्थ्य) संजय शिंदे ने बताया कि अस्पताल सार्वजनिक निजी भागीदारी(थ्री पी)मॉडल पर चलाया जाएगा ।इसके लिए प्लेटिनम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ३० साल का करार किया गया है ।यह कंपनी ठाणे में गंगूबाई हॉस्पिटल चला रही है ।आयुक्त काटकर ने कहा कि ठाणे में इस मॉडल से कैशलेश हॉस्पिटल प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था,जो पूरी तरह सफल रहा है। ठाणे के बाद मीरा भायंदर में यह दूसरा हॉस्पिटल होगा। उपायुक्त शिंदे ने बताया कि अस्पताल में ज्योतिबा फूले आरोग्य जीवनदायी योजना तथा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी यानी पीला,केसरी,सफेद राशन कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड धारक परिवारों का मुफ्त में ओपीडी, डैग्नोस्ट (निदान), दवा- उपचार और सर्जरी होगा ।गैर राशन कार्ड धारकों का इलाज सशुल्क होगा ।लेकिन केंद्र सरकार की निर्धारित उपचार दरों से १३ फीसदी कम होगा ।उपायुक्त शिंदे ने बताया की इस अस्पताल में कैंसर,किडनी,हार्ट जैसी बडी बीमारियों की जांच,उपचार और सर्जरी,आईसीयू,पोस्ट ऑपरेटिव,एसी जनरल बेड,कैज्युलिटी बेड की सुविधा रहेगी। मीरा रोड के इंदिरा गांधी मनपा अस्पताल में ३० फीसदी दर पर जांच होगी ।इसके लिए कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिट्स के साथ मनपा ने अनुबंध किया है ।कंपनी के निदेशक गोरक्ष नाइकोली ने बताया कि केंद्र सरकार की तय दर से २ फीसदी कम में जांच होगी,जो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की कीमतों से ६०/७० फीसदी कम होती है ।रक्त,एक्सरे, सीटी स्कैन,एमआरआई आदि जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

अवैध रुप से रह रही बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार

जेकेएस संवाददाता

मीरा रोड: भाईंदर के काशी मिरा पुलिस स्टेशन के पेंकरपाडा इलाके में रहने वाली पांच बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. काशी मिरा पुलिस को सूचना मिली थी कि पेनकर पाडा इलाके में कुछ कुछ बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं. मिली

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उसकी जांच की और जाल बिछाया पेनकर पाडा में जांच करने पर तौहीमा सोहेल मंडल, शिबली मोहम्मद यासिर खान और महरूफा सोहेल मंडल उर्फ गीता (तीनों हीराजी गणपत चाल, दत्त मंदिर के पास) जबकि सबीना यास्मीन अकबर हुसैन और अनामिका उर्फ मुन्नी शाहजहां मंड दोनों रहते थे। काशी मीरा पुलिस ने म्हात्रे निवास, पेनकारपाडा से भारत में अवैध रूप से रह रही पांच बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं पिछले कुछ दिनों से बिना किसी आधिकारिक निवास प्रमाण के भारत में रह रही थीं। इस अपराध की आगे की जांच काशी मिरा पोलीस ठाणे के सब-इंस्पेक्टर अभिजीत लांडे कर रहे हैं.

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक-मुद्रक सीमा गुप्ता के लिए (प्रिंटींग) सागर प्रिंट एंड प्रोसेस, प्रगती इंडस्ट्रीयल, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००११ से मुद्रित १०१, १ला माला सेक्टर ११ सी-२८, टी.एम.टी. बस स्टॉप के पीछे, शांतिनगर, मीरारोड (पूर्व), जिला थाना ४०११०७ (महाराष्ट्र) से प्रकाशित संपादक - सीमा गुप्ता, सलाहकार : सुधाकर डी., पी.आर.बी अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चन के लिए उत्तरदायी है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र केवल जिला थाना रहेगा।
RNI NO. MAHHIN/2004/17839 Mob.No.9757262120 Email :newsjankalyanseva@gmail.com Jankalyan Seva GST No. 27AGUPG9011BIZI